



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2008/अग्राहायण 4, 1930

No. 420]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2008/AGRAHAYANA 4, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2008

**विषय :** चीन जन. गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड तथा यू एस ए के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत।

सं. 14/6/2008-डीजीएडी.—मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड, नई दिल्ली ने चीन जन. गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड तथा यू एस ए (जिन्हें एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों (जिन्हें एतदपश्चात सम्बद्ध वस्तुएं कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसरण में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्यमान है, अतः प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में कथित पाटन की मौजूदगी, सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने के लिए; जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी; कथित पाटन और उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच की एतद्वारा शुरुआत करते हैं।

## घरेलू उद्योग

2. आवेदन मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन में आवेदकों को योगदान 80 प्रतिशत का है, अतः उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जाँच हेतु मामला दायर करने का अधिकार है। सम्बद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक मैसर्स सेलम इस्पात संयंत्र, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., सेलम है।

## विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण, जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड एवं यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के 60 मिमी अथवा अधिक चौड़ाई वाले कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, जिन पर और कार्य करके कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रिड्यूस्ड) (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) किया जाता है, है।

4. विचाराधीन उत्पाद में उपर्युक्त विवरण वाली स्टेनलेस स्टील कॉइल, चदरे तथा प्लेटें शामिल हैं। वस्तुएं वस्तुओं का उपयोग व्हाइट गुड्स, प्रसंस्कृत उपकरणों, डेयरी उपकरणों, आटोमोटिव संघटकों, रेल कार्टों, मेट्रो के डिब्बों के विनिर्माण, वास्तुकला, भवनों एवं निर्माण कार्य आदि में किया जाता है।

संबद्ध वस्तुएं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 72 में उपशीर्ष 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 तथा 7219.90 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

मूल सीमाशुल्क 5 प्रतिशत है।

## समान वस्तुएं

5. आवेदक ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के "समान वस्तुएं" हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं भारतीय आयातकों द्वारा संबद्ध देशों/भूभागों से आयातित संबद्ध उत्पादों का उपयोग भारत के उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध उत्पादों एवं आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पादों की भौतिक विशेषताओं, उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम उपयोग में सामान्य समानताएं हैं। संबद्ध आयात एक दूसरे से और अन्य देशों से आयातित उत्पादों से और दोनों मिलकर घरेलू समान उत्पाद से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और आयातित देशों से उत्पादित उत्पाद वाणिज्यिक एवं तकनीकी दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं; अतः ये पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत यथा परिकल्पित "समान वस्तुएं" हैं।

## शामिल देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन गण, जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड और यू एस ए हैं।

## सामान्य मूल्य

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन गण (गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण) में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने पहले विकल्प के तौर पर किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था

वाले तीसरे देश में घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। आवेदक ने यह प्रस्ताव किया है कि जापान को समुचित अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाए, क्योंकि यह दावा किया गया है कि चीन में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण की क्षमता जापान की विनिर्माण सुविधाओं के लगभग समान हैं। अतः जापान को सहोदर देश मानने का प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि इसकी उद्योग संरचना, संयंत्रों की औसत क्षमता एवं लागत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी तार्किक दृष्टि से चीन की उद्योग संरचना, संयंत्रों की औसत क्षमता एवं लागत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के लगभग समान है।

जहाँ तक अन्य संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का संबंध है, यह प्रकाशित कीमतों (पर विचार करते हुए अनुमानित उत्पादन लागत) पर आधारित है। प्राधिकारी ने प्रकाशित कीमतों (साइबेक्स एक्जिम सॉल्यूशन्स प्रा० लि०), जिसे आवेदक ने उपलब्ध कराया है, के आधार पर संबद्ध देशों (चीन जचन गण को छोड़कर) में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्ट्या विचार किया है और जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा इसी पर विचार किया गया है।

### निर्यात कीमत

8. निर्यात कीमतों का दावा साइबेक्स एक्जिम सॉल्यूशन्स प्रा० लि० से प्राप्त आंकड़ों, जिन्हें गौण स्रोतों से संकलित किया गया है, के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए कीमत समायोजनों का दावा निर्यात वाले देश में समुद्री मालभाड़े, पत्तन प्रहस्तन तथा पत्तन प्रभार, कमीशन आदि के आधार पर किया गया है। आवेदक द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं हेतु निर्यात कीमतों एवं समायोजनों के संबंध में किए गए दावे का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है।

### पाटन मार्जिन

9. इस बात का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों की तुलना में काफी अधिक हैं, जो प्रथम दृष्ट्या इंगित करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

### क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के कारण बाजार हिस्से में गिरावट, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, गंवाई गई बिक्री और जांच अवधि (पी ओ आई) के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आई उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई क्षति का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हुई वास्तविक क्षति का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है।

### जांच अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जनवरी 2007 से 31 दिसम्बर 2007 (12 माह) है। तथापि क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल 2004 - मार्च 2005, अप्रैल 2005 - मार्च 2006 और अप्रैल 2006 - मार्च 2007 को शामिल किया जाएगा।

### भूतलक्षी प्रभाव से शुल्कों का अधिरोपण

12. आवेदक ने भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध इस आधार पर किया है कि पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति का इतिहास रहा है। यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामले में संबद्ध देशों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का न केवल पाटन किया जा रहा है, बल्कि पिछली जांच में भी अधिकांश संबद्ध देशों ने पाटन किया था। यह आरोप लगाया गया है कि पिछले 3 - 4 वर्षों से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन किया जाता रहा है। हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपना निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

### सूचना प्रस्तुत करना

13. संबंधित ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों और घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे समस्त सूचना निर्धारित प्रपत्र व ढंग से प्रस्तुत कर सकें। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार निम्नलिखित को लिख सकता है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी,  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
वाणिज्य विभाग,  
कमरा नं 240  
उद्योग भवन,  
नई दिल्ली-110107

### समय सीमा

14. इस जांच से संबंधित कोई भी सूचना प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर लिखित में भेजी जाए जो उन्हें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 40 दिनों से अनधिक अवधि में प्राप्त हो जाए। हितबद्ध पक्षकार पैरा 7 में उल्लिखित शर्त के अनुसरण में सहोदर देश के चयन के संबंध में अपनी टिप्पणी यह अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसरण में कोई भी पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

16. सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(1) के अनुसरण में, प्रदत्त सूचना का गोपनीय और अगोपनीय पाठ नियम 7(2) के अनुसरण में गोपनीय सूचना हेतु प्रस्तुत करेंगे।

17. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार जानकारी उपलब्ध कराने से मना करता है अथवा समुचित अवधि के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उन्हें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को वह सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2008

**Subject : Initiation of Anti-Dumping investigations concerning imports of Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel originating in or Exported from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA.**

**No. 14/6/2008-DGAD.**—M/s. Jindal Stainless Ltd., New Delhi has filed an application before the Designated Authority (hereinafter refer to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (herein after referred to as Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning alleged dumping of Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (hereinafter referred to as subject countries).

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Domestic Industry**

2. Application has been filed by M/s Jindal Stainless Ltd., New Delhi on behalf of the domestic industry. As per the evidence available, the applicants accounts for 80% of the total domestic productions and, therefore, has the standing to file the case for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules. The other producer of the subject goods is M/s Salem Steel Plant, Steel Authority of India Ltd., Salem.

**Product Under Consideration**

3. The product under consideration is "Cold-rolled Flat products of stainless steel of the width of 600 mm or more of all series further worked then Cold rolled (cold

4665 GI/08-2

reduced) (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA.

4. The product under consideration comprises of stainless steel coil, sheets and plates of above description. The subject goods are used for manufacturer of white goods, processed equipment, dairy equipment, automotive components, rail carts, metro coaches, architecture, building and construction, etc.

The subject goods are classified under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 under the Sub-heading 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

The basic Customs Duty is 5 per cent.

#### **Like Articles**

5. The applicant has claimed that the goods produced by them are “like articles” to the goods originating in or exported from the subject countries. The products produced by the applicant and the subject products imported from the subject countries/territories by Indian importers are being used interchangeably by the consumers in India. There are general similarities in physical characteristics, production process, end use in the subject products imported from the subject countries and that produced by the applicant. The subject imports compete directly with each other and with those imported from other countries and together compete with the domestic like product. Thus, the subject products produced in the domestic industry and imported from the subject countries are commercially and technically substitutable and therefore, are “like articles” as envisaged under Anti Dumping Rules.

#### **Countries Involved**

6. The countries involved in the present investigations are China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA.

#### **Normal Value**

7. The Authority notes that the applicant has claimed normal value of subject goods in China PR (being a Non Market Economy country) as per Para 7 of Annexure –I to the Anti Dumping Rules. The applicant has taken normal value based on domestic selling prices in a market economy third country as a first alternative. It has been proposed by the applicant that Japan be taken as an appropriate market economy third country as it has been claimed that the capacity in China for manufacturing the subject goods is close to the manufacturing facility in Japan. Japan is, therefore, proposed as surrogate country as the industry structure, the average capacity of plants, the cost structure, the production process and the technology are reasonably and fairly close to that found in China.

Regarding normal value of subject goods in other subject countries, it is based on (estimated cost of production by considering) published prices. The Authority has

prima facie considered the normal value of subject goods in subject countries (except China PR) on the basis of published prices (Cybex Exim Solutions Pvt. Ltd.) as made available by the applicant and it has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

### **Export Price**

8. The export prices have been claimed on the basis of data obtained from Cybex Exim Solutions Pvt. Ltd., Noida as compiled from secondary sources. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight in the country of export, port handling and port charges, commission, etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of export prices and the adjustments claimed by the applicant for the subject goods from the subject countries.

### **Dumping Margin**

9. There is sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices indicating prima facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

### **Injury and Causal Link**

10. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of fall in their market share because of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, lost sales and substantial decline in profitability for the domestic industry during POI. There is sufficient prima facie evidence of the material injury being suffered by the applicant caused by dumped imports from subject countries.

### **Period of Investigation**

11. The Period of Investigation (POI) for the purpose of present investigation is 01<sup>st</sup> January, 2007 to 31<sup>st</sup> December, 2007 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the period April 2004 - March 2005, April 2005 - March 2006, April 2006 - March 2007.

### **Retrospective imposition of duties**

12. Applicant has requested for retrospective imposition of duty on the ground that there is history of dumping and injury to domestic industry. It was also stated that the product under consideration is not only being dumped by the subject countries in the present case but has also been dumped by the most of the subject countries in the previous investigation as well. It is alleged that the subject goods have been continuously dumped for the past 3-4 years. The interested parties may make their submissions in this regard.

**Submission of information**

13. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
Room No.240,  
Udyog Bhavan,  
New Delhi-110 107.**

**Time limit**

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. Interested parties may offer their comments, if any, on the selection of surrogate country in terms of Para 7 within 15 days of the issue of the Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**Inspection of Public File**

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rules supra.

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority